स्टेट रिप्रजेंटेड बाई सी. बी. आई.

बनाम

अनिल शर्मा

सितंबर 3,1997

[एम. के. मुखर्जी और के. टी. थॉमस, न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता - धारा 436 - भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में अग्रिम जमानत-यदि संदिग्ध व्यक्ति को पता है कि वह गिरफ्तारी-पूर्व जमानत आदेश द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है, तो पूछताछ से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकती है जो अन्यथा होने की संभावना है। अग्रिम जमानत देने के लिए प्राप्त विचार-विमर्श गिरफ्तारी के बाद जमानत देने के समान नहीं होना चाहिए।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-धारा 13(2)।

प्रतिवादी जो एक सांसद, एक पूर्व मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री का बेटा था को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपराध के एक मामले में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी। सी.बी.आई. द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील की गई।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत आदेश देकर संहिता की धारा 438 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने में खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर इस तरह विचार किया मानो वह गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत देने की प्रार्थना पर विचार कर रहा हो। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खुद को इस सिद्धांत की याद दिलाई कि "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जमानत और जेल नहीं एक सामान्य नियम है"। अग्रिम जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय न्यायालय को जिस विचार पर विचार करना चाहिए, वह गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा करने के आवेदन के समान नहीं होना चाहिए। किसी भी दर पर एकल न्यायाधीश को सीबीआई द्वारा व्यक्त की गई आशंका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था (कि प्रतिवादी गवाहों को प्रभावित करेगा) क्योंकि यह सभी मामलों में सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ किया जा सकता है। प्रतिवादी के उच्च पद और उस अवधि से संबंधित आरोप की प्रकृति पर विचार करते समय आशंका काफी उचित थी, जिसके दौरान वह इस पद पर था। [740-सी, ई-एफ]

2. हिरासत में पूछताछ किसी ऐसे संदिग्ध से पूछताछ करने की तुलना में गुणात्मक रूप से अधिक पूछताछ उन्मुख है जो संहिता की धारा

438 के तहत अनुकूल आदेश के साथ अच्छी तरह से फंसा हुआ है। ऐसे मामले में संदिग्ध व्यक्ति से प्रभावी पूछताछ कई उपयोगी सूचनाओं और सामग्रियों को उजागर करने में काफी फायदेमंद होती है, जिन्हें छुपाया गया होता। इस तरह की पूछताछ में सफलता नहीं मिलेगी यदि संदिग्ध व्यक्ति को पता हो कि पूछताछ के दौरान वह अच्छी तरह से संरक्षित है और गिरफ्तारी पूर्व जमानत आदेश से अछूता है। ऐसी स्थिति में अक्सर पूछताछ महज एक अनुष्ठान अदायगी बनकर रह जाती है। यह तर्क कि हिरासत में पूछताछ व्यक्ति को थर्ड डिग्री तरीकों के अधीन होने के खतरे से भरा है, को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह का तर्क सभी आपराधिक मामलों में सभी आरोपियों द्वारा दिया जा सकता है। अदालत को यह मानना होगा कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारी खुद को जिम्मेदार तरीके से आचरण करेंगे और जिन्हें अपराधों को शांत करने का काम सौंपा गया है, वे खुद को अपराधियों के रूप में आचरण नहीं करेंगे। [739-जी-एच, 740-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 811/1997

आपराधिक एमपी क्रमांक 1217/1996 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.11.96 से।

के.एन. भट्ट, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, (पल्लव शिशोदिया), पी. परमेश्वरन, अपीलकर्ता की ओर से।

आर.के. जैन, विजय बहुगुणा, अनीस सुहरावर्दी, राजेश कुमार, सुश्री शमाना अनीस, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय थॉमस, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

यह अपील केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत प्रतिवादी के पक्ष में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए गिरफ्तारी पूर्व आदेश को चुनौती देने के लिए है। प्रतिवादी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पूर्व मंत्री थे और उन्होंने लगभग तीन वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। इसके अलावा वह उस राज्य की विधान सभा के सदस्य भी हैं। उनके पिता (सुखराम) केंद्रीय दूरसंचार मंत्री थे। सीबीआई प्रतिवादी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत अपराध के मामले की जांच इस आरोप पर कर रही है कि प्रतिवादी ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। जब जांच प्रगति पर थी तो प्रतिवादी ने अग्रिम जमानत के आदेश के लिए हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से संपर्क किया। सीबीआई द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन शर्तों के

अधीन आदेश दिया कि प्रतिवादी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएगा, और अपना पासपोर्ट सीबीआई को सौंप देगा आदि।

प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए आरोप, वर्तमान में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी हैं कि उसने आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले 16,65,000 रु. की संपत्ति अर्जित की थी, जो उसके आधे तक भी नहीं पहुंच सके। सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि संपत्ति प्रतिवादी द्वारा अवैध तरीकों से बनाई गई है और "श्री सुखराम द्वारा अपने बेटे के नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण की ओर इशारा करने वाले स्पष्ट सबूत हैं"। सीबीआई के अनुसार, प्रतिवादी का यह उच्च पदों पर भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है और ऐसे मामले में अग्रिम जमानत का आदेश कभी नहीं दिया जाना चाहिए था।

हमने श्री के.एन. भट्ट, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सुना, जिन्होंने सीबीआई के लिए बहस की और श्री आर.के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने प्रतिवादी के लिए बहस की। हमें केस-डायरी को पढ़ने की जरूरत महसूस हुई जो हमें सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराई गई थी। हमने उसका अध्ययन किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में विवेक का प्रयोग करके पूरी तरह से गलत किया है। उनके अनुसार, प्रतिवादी के जिम्मेदार और उच्च पद और उसके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले व्यापक प्रभाव और

अग्रिम जमानत के आदेश से लैस किसी व्यक्ति से पूछताछ करते समय जांच एजेंसी को होने वाली बड़ी बाधा को ध्यान में रखते हुए, धारा 438 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग कभी भी प्रतिवादी के पक्ष में नहीं किया जाना चाहिए था।

दूसरी ओर श्री आर.के. जैन ने आदेश का बचाव करते हुए दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है क्योंकि इसे विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय ने पारित किया था।

हमें सीबीआई की इस बात में दम नजर आता है कि हिरासत में की गई पूछताछ किसी ऐसे संदिग्ध से पूछताछ करने की तुलना में गुणात्मक रूप से अधिक पूछताछ है, जो संहिता की धारा 438 के तहत अनुकूल आदेश के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे मामले में संदिग्ध व्यक्ति से प्रभावी पूछताछ कई उपयोगी सूचनाओं और सामग्रियों को उजागर करने में काफी फायदेमंद होती है, जिन्हें छुपाया गया होता। इस तरह की पूछताछ में सफलता नहीं मिलेगी यदि संदिग्ध व्यक्ति जानता है कि पूछताछ के दौरान वह गिरफ्तारी पूर्व जमानत द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित है। अक्सर ऐसी स्थिति में पूछताछ महज़ एक रस्म बनकर रह जाती है। इस तर्क को मानने की जरूरत नहीं है कि हिरासत में पूछताछ करने पर व्यक्ति को थर्ड डिग्री तरीकों का सहारा लेने का खतरा

रहता है। क्योंकि, इस तरह का तर्क सभी आपराधिक मामलों में सभी आरोपियों द्वारा दिया जा सकता है। न्यायालय को यह मानना होगा कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारी खुद को जिम्मेदार तरीके से संचालित करेंगे और जिन्हें अपराधों से मुक्ति दिलाने का काम सौंपा गया है, वे खुद को अपराधी के रूप में आचरण नहीं करेंगे।

उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर ऐसे विचार किया मानो वह गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत देने की प्रार्थना पर विचार कर रहा हो। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने खुद को इस सिद्धांत की याद दिलाई कि "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जमानत और जेल नहीं एक सामान्य नियम है" और फिर इस प्रकार कहा:

> "जब तक असाधारण परिस्थितियों को अदालत के ध्यान में नहीं लाया जाता है जो उचित जांच और निष्पक्ष सुनवाई को विफल कर सकती हैं, अदालत ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार नहीं करेगी जो वर्तमान मामले में मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोपी नहीं है, इस न्यायालय के संज्ञान में ऐसी कोई भी असाधारण परिस्थिति नहीं लाई गई है जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए उचित जांच को विफल कर सके।"

गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय उपरोक्त टिप्पणियाँ अधिक सार्थक हैं। अग्रिम जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय न्यायालय को जो विचार करना चाहिए, वह गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा करने के आवेदन के समान नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर एकल न्यायाधीश को सीबीआई द्वारा व्यक्त की गई आशंका (कि प्रतिवादी गवाहों को प्रभावित करेगा) को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, जो कि सभी मामलों में सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ की जा सकती है। प्रतिवादी के उच्च पद और उस अवधि से संबंधित आरोप की प्रकृति पर विचार करते समय आशंका काफी उचित थी, जिसके दौरान वह इस पद पर था।

केस-डायरी पत्रावली के अवलोकन सहित हमारे गहन विचार-विमर्श के बाद, हम निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को गिरफ्तारी से पहले जमानत आदेश देकर संहिता की धारा 438 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है। इसलिए, हम विवादित आदेश को खारिज करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

एल.एम.ए.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।